श्री शिव कुमार मिश्र : श्रीमान मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1987 (INSERTION OF NEW ARTICLE 30A (Etc.)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : श्रीमन्, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1985 (TO AMEND ARTICLE 311)—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): We shall now take up further consideration of the Bill moved by Dr. Bapu Kaldate on 13th March, 1987. Shri Bir Bhadra Pratap Singh to continue his speech.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH (Uttar Pradesh): Sir, last time, while speaking on this Bill, I said that the proviso provided under the Constitution was fully justifiable, was reasonable, was rational and was grounded upon substantial requirements and, therefore, I supported that proviso. So, in the general scheme, the opportunity has been rightly abridged in the proviso. Now, I will place three provisos to justify my argument and I will explain how it is justifiable.

Now, the first proviso says, "Where a person is dismissed, removed or reduced in rank on the ground of conduct that has led to his conviction on a criminal charge, etc etc.." Now, why should it be argued at all that a criminal should be allowed to continue in Government service? If that is the only rationale behind this provise then any argument to the contrary, that is, that a criminal person must be allowed to continue in Government service would be a preposterous proposition and I think Dr. Bapu Kaldate will agree with my contention that in no case should a criminal be allowed to continue in Government service and if a criminal is allowed after conviction, a second innings is provided in the general scheme of (1) and (2). Then it will take another twenty years and by the time the superannuation comes, the criminal will continue in service. Therefore, the proposition that this proviso is unreasonable is an untenable proposition. Now, Sir, I come to proviso (c) to article 311(2) which says like this:

> "where the President or the Governor as the case may be is satisfied that in the interest of security of the State it is not expedient to hold such an inquiry."

Now, the highest authority in the State—not in any way a partisan authority, because both the President and the Governor, whatever may be the mode of their appointment to their respective posts, are supposed to be Constitutional heads and impartial authorities—should be satisfied and the power vested in them requires that he is to be satisfied that in the interest of the security of the State it is not expedient to hold such an inquiry. So, I think no reasonable man in this country would question the wisdom which lies in such an authority who is the highest authority under the Constitution, who is the Constitutional authority in the State, and he does it for a limited purpose, that is, in the interest of the security of the State.

Now, I come to the most controversial part of it; that is, sub-section (b). Now, the power may be different, but the safeguard is provided in sub-section (b) itself and if some statute provides a safeguard in itself, then it is a double safeguard. Probably that was subjected to attack when Dr. Bapu Kaldate enunciated this amendment under which the authority empowered to dismiss or remove a person or

reduce him in rank is satisfied, for some reason to be recorded by that authority in writing, that it is not reasonably practicable to hold an inquiry. Now, the safeguard is provided here in the words, "for reasons to be recorded by that authority in writing". This is a sufficient safeguard because the moment the law says that for some reasons to be recorded by the authority in writing, which is dispensing with the inquiry that the inquiry should not be held, that writing becomes a subject matter in the judiciary. As I have said, wherever a statute has provided "for reasons to be recorded by the authority", that authority can do this. Then, at least that much writing by that authority (Interduption) The moment it is found that the reason recodred by the third party is not germane or is extraneous or malicious or is bad or there is any other consideration, that authority can strike it down. There are a large number of grounds provided under the law. Wherever it has been provided in various statutes that first reasons should be recorded in writing one can do this and that, that becomes the subject-matter of judicial scrutiny. Once it becomes the subject matter of judicial scrutiny, then the High Court or the Supreme Court can immediately examine whether that authority has exercised that power vested in him. There are many other grounds about the powers of the High Courts and Supreme Court. You cannot argue that proviso (b) does not contain safeguards in itself. You cannot argue that it is arbitrary, this is not a reasonable power. I think the Supreme Court was quite right in holding this view. It is not a new amendment. This is not a new proviso. If the statute in the proviso provides adequate safeguards within itself, then there is no room for any challenge to it, And that is why my contention was that a proviso with sufficient safeguards should be upheld because it is founded, it is grounded, it was given by the founding fathers of the Indian Constitution as safeguard, to improve the standard services. It will not deteriorate, it will improve their services, it will take away bad smell out of it and keep it healthy. That is why I have always supported this.

With this, I think Mr Bapu Kaldate will seriously consider this in view of the arguments advanced. I think he is subject to reason.

श्री पशुपति नाथ सुकुल (उत्तर प्रदेश : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बापू कालदाते जी के द्वारा लाए गए विधेयक का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह विधेयक जिन भावनाओं से ओत-प्रोत है वह भावनाएं आज हमारे देश के समस्त सरकारी कर्मचारियों की हैं और जो दूसरे कमचारी हैं उनकी भी हैं। राज्य कर्मचारियों के बारे में तो कम से कम मैं जानता हूं। मैं उनके अखिल भारतीय महासंघ का 13–14 साल अध्यक्ष रहा और हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ के मांग पत्र में ये मांगें हैं तथा पिछले 20 साल से यही मांगें है। मैं अपने को उन मांगों से जोड़ता हूं और जिस भावना से विधेयक लाये हैं उस भावना से में अपने को जोड़ता हूं। यह न्याय का पहला सिद्धांत है कि बिना बचाव का अवसर दिए किसी को दंड नहीं दिया जा सकता । आपको उसे बचाव करने का अवसर देना होगा । आप दंडित करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस देंगे। आपको उसे चार्जशीट आरोप–पत्र देना होगा और उसकी सुनवाई करनी होगी । अगर आप ये तीन काम नहीं करते हैं, न उसे शो काज नोटिस देते हैं, न चार्ज शीट देते हैं और न उसको हीयरिंग का अवसर देते हैं और उसको नौकरी से निकाल देते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता । अभी हमारे मित्र बीरभद्र प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि इसके कारण सेवाओं में सुधार होगा, आप क्या बात कर रहे हैं । यह जो प्रावधान है हमारे संविधान में यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 से इसका समावेश किया गया है । यह कालोनियल जोरुल था उसका सिद्धांत है। जिस नौकरशाही को अपने

[श्री पशुपति नाथ शुकुल]

पूर्ण नियंत्रण में रख करके इस देश को एक्सप्लायट करना चाहते थे, देश का शोषण करना चाहते थे अंग्रेज, वह अंग्रेज इस प्रकार के नियम बनाकर चल रहे थे और आज उन्हीं नियमों का समावेश संविधान में आपने कर लिया है। आज जैसा कि इंग्लैंड में हैं कि वहां के किसी भी सिविल सवण्ट की नौकरी क्राउन के प्लीज़र पर होगी अर्थात् राजा या रानी के प्रसाद-पर्यन्त वह सेवा कर सकता है, वही सिद्धांत आपने यहां रखा है कि अगर कोई केन्द्रीय कर्मचारी है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त काम करेगा और अगर कोई राज्य सरकार का कर्मचारी है तो वह राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त काम करेगा और यह 311 अनुच्छेद का जो प्रावधान है, जिसका उल्लेख किया गया है विधेयक में, इसके द्वारा राज्यपाल या राष्ट्रपति कभी भी किसी की सेवा खतम कर सकता है और चूंकि यह संविधान में है, इसलिए इसका इण्टरप्रिटेशन सुप्रिम-कोर्ट भी करेगा हाईकोर्ट भी करेगा। जब तक यह संविधान में नियम है, यह व्यवस्था है, तब तक वह लागू होगी और लागू की जायगी। तो उच्चतम न्यायालयों का जो इण्टरप्रिटेशन है या जो जजमेन्ट है, वह आपके संविधान पर आधारित है और आपने संविधान ही ऐसा बना रखा है कि वहां पर किसी को भी आप निकाल सकते हैं, सैकड़ों कर्मचारियों की सेवाएं देश में इनके अधीन समाप्त की जा चुकी है।

महोदय, आज बीर भद्र प्रताप जी जो यह कह रहे थे कि इससे सुधार होगा। तो सन् 1935 से लेकर आज तक तो कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि मांग आ रही है कि इसको समाप्त किया जाये, इसको हटाया जाये। बापू कालदाते जी भी मांग कर रहे हैं कि इसको हटाया जाय। आप अगर बिना किसी को बचाव का अवसर दिए सेवा जैसी महत्वपूर्ण चीज से निकालने की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप समाजवादी नहीं हैं। आज हमारा जो संविधान हमारा जो गणतंत्र है, वह सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसमें सोशलिज्म शब्द क्यों लाए हैं? अगर सामाजिक न्याय नहीं दे सकते तो आपको समाजवादी अपने आपको कहने का कोई हक नहीं है। ....(व्यवधान) आप मनमाने ढंग से काम कर सकें और उसको एक्सप्लायट कर सकें ताकि वह बेचारा इसी डर से कि मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायंगी राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश से और वह काम करता रहेगा तो मैं इस मामले में कहूंगा कि आप घोर असमाजवादी हैं, कालोनियल जो रुल है, उसके पिछलग्गू हैं। शेर की खाल ओढ़ लेने से गीदड़ शेर नहीं हो जाता। गीदड़ रहता है और शेर शेर रहता है। मैं कहूंगा कि दूसरी जो डेमोक्रेसी हैं, उनके नियम आपको लेने चाहिएं। इसी संबंध में मैंने सन 1983 में एक रेजुलेशन दिया था गैर-सरकारी और उस पर बहस करायी थी कि सरकारी कर्मचारियों को लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिएं, राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिएं और उसका सारी पार्टियों ने समर्थन किया था। उस समय जो गृह मंत्री बोले थे वैंकटसुबया जी, उन्होंने कहा था कि मैं एग्री करता हूं, लेकिन आप इसे वापिस ले लीजिए, सरकार इस पर सोचेगी। तो जहां तक अपने कर्मचारियों या मजदूरों के शोषण का सवाल है, मैं कभी आपके साथ अलग नहीं हो सकता और अगर मुझे अपनी भावनाएं प्रकट करने का अवसर दिया गया तो मैं अपनी भावनाएं अवश्य प्रकट करुंगा, लेकिन यह दूसरी बात है कि व्हिप होगा तो मैं अपनी पार्टी को वोट दूंगा पार्टी का एक वफादार सैनिक होने के नाते ...(व्यवधान)...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: (उत्तर प्रदेश) अपनी अंतरात्मा का इस्तेमाल नहीं करेंगे?

श्री पशुपति नाथ सुकुल: : अन्तरात्मा का इस्तेमाल मैं इस समय कर रहा हूं और उस समय मैं नैतिकता का इस्तेमाल करुंगा।

श्री वीरभद्र प्रताप सिंह: डबल स्टेण्डर्ड...(व्यवधान)...

श्री पशुपति नाथ मुकुल : डबल स्टेण्डर्ड तो तब होता, जब एक बात को छिपाना और बोलता कुछ। जब बोलने का अवसर देंगे तो हिमायत करुंगा। ऐसा नहीं है कि मजदूरों और कर्मचारियों की हिमायत करने के लिए केवल विरोध पक्ष के लोग बैठे हैं। यह धारणा अगर किसी की है इस देश में, तो गलत धारणा है। हमारी रुलिंग पार्टी में तामम ऐसे लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़े हैं और मैं तो पांच साल जेल में रहा हूं।

मैं नहीं समझता कि इस सदन में बैठने वाला कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी के पक्ष में पांच साल जेल में रहा हो। मैं तो कभी बदल ही नहीं सकता। मेरी धारणा नहीं बदल सकती। न ही उनका शोशण करने की मेरी इच्छा है। मैं कुछ और बन जाऊंगा तो मैं उनका शोषण करने लगूंगा ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। इसलिए, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस सदन के सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां तक यह सवाल है, जहां तक यह व्यवस्था है जैसा कि इस विधेयक में दिया गया है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख)(ग) का लोप कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे कोई बेईमान है, कोई राष्ट्र-विरोधी है, कोई बदमाश है तो आपके पास व्यवस्था है कि अनुछेच्द 309 के अंतर्गत आप कार्यवाही कर सकते हैं, आप उस को चार्ज-शीट कर सकते हैं, उसको आप जरूरी हो तो नौकरी से निकाल सकते हैं। तो जब आपके हाथ में अधिकार है कि न्याय की परंपरा का अनुसरण करते हुए उसे दंडित कर सकें तो आप उस मार्ग से चलिए। फिर आप शार्ट-कट से जाकर उसको क्यों निकालना चाहते हैं, बिना सुनवाई का अवसर दिए क्यों निकालना चाहते हैं, संविधान में यह व्यवस्था रखना ही स्पष्ट करता है कि आपके मन में डर है। मैं इसको मानूंगा नहीं। मैं इस संविधान को, कम से कम सरकारी कर्मचारियों के प्रति जो हमारी सरकार का रवैया है, केन्द्रीय सरकार का हो या राज्य सरकारों का, तब तक उसे उचित नहीं मानता जब तक कि आप इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करते। न्याय के समक्ष समुचित फैसला होने का अवसर सभी को मिलना चाहिए। उसे दंडित करने से पहले उसको कारण बताओ नोटिस मिलना चाहिए, आरोप-पत्र मिलना चाहिए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि आप समाजवादी हैं और मैं आपको उस ऐक्सटेंट तक समाजवादी नहीं मानता हूं चाहे कहने के लिए आप अपने आपको कार्ल मार्क्स बताएं, तो भी मैं नहीं मानूंगा।

श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा जो सरकारी कर्मचारी हैं वे ही इस देश का शासन तंत्र चला रहे हैं। हम और आप यहां बैठकर बातें करते हैं, हम शासन नहीं चला रहे हैं। आप आई०आर०डी०पी० का लोन भी तय कर देंगे और बाद में सवाल भी उठा देंगे कि उचित ढंग से क्यों नहीं दिया जा रहा है। ठीक से क्यों क्यों नहीं बाटा जा रहा है। तो जो ऐक्जीक्यूशन है वह ज्यादा आवश्यक है, ऐक्जीक्यूशन आप नहीं करते हैं। आप तो केवल प्लान बनाते हैं, ऐक्जीक्यूशन करता है कर्मचारी जो कि रेलेवेंट लेवल का है, लोवेस्ट लेवल का है चाहे वह पंचायत का सेवक हो, बी०एल०डब्लू या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षक हो या लेखपाल हो या पटवारी हो। इसीलिए काम वे करते हैं, वे आपके निर्णयों को कार्यरूप में परिणत करते हैं। वे अच्छा करते हैं तो आप अपनी शक्ल अच्छी देखते हैं आइने में वे खराब करते हैं तो सरकार की शक्ल खराब दिखाई देती है। मंत्रिमंडल यहां बैठकर निर्णय लेता रहे, लोकसभा या राज्य सभा में बैठकर लंबी लंबी स्पीचें दे, लेकिन केवल उसी से काम नहीं चलता। जब लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या होता है? जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो क्या होता है, जब पापुलर गवर्नमेंट नहीं होती तो भी सरकार का सारा काम चलता रहता है। आप तो काम करने वाले कर्मचारियों के मालिक हैं। सरकार तो बस की मालिक है, लेकिन बस को कौन चलता है? ड्राइवर और कंडक्टर। ड्राइवर और कंडक्टर न हों तो मालिक

[श्री पशुपति नाथ सुकुल]

घर में बैठा रहेगा, बस खड़ी रहेगी। उस बस को चलाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रशासन अच्छा हो, शासन अच्छा हो तो उसके लिए जिनके कंधों पर आपकी पालकी उठाई जा रही है, जिनके कंधों पर आपकी शासन की बैलगाड़ी चल रही है, उनके साथ तो न्याय करें उनका आप साथ दें। आज क्या व्यवस्था है? जो संविधान के अंतर्गत स्टेट एम्पलाई की परिभाषा है उसमें राज्य कर्मचारी भी आता है। केन्द्रीय कर्मचारी भी आता है, लोकल बाडी का कर्मचारी भी आता है, सारी सेवाओं के सारे कर्मचारी स्टेट एक्सप्लाइज की परिभाषा में आते हैं। लेकिन संविधान में एक शब्द आया है 'स्टेट एम्पलाइज' लेकिन आज मध्य प्रदेश के एम्पलाइज को कोई तनख्वाह मिल रही है, उत्तर प्रदेश के एम्पलाइज को कोई तनख्वाह मिल रही है, उड़ीसा में जाइये तो आप देखेंगे कि सबसे कम तनख्वाह मिल रही है, भत्ते सब के अलग-अलग हैं, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी कुछ पा रहे है और राज्य सरकार के कर्मचारी कुछ पा रहे हैं और लोकल बाडी के कर्मचारी कुछ पा रहे हैं। लोकल बाडी के कर्मचारियों की तो और भी खराब हालत है। सब स्टेट एम्प्लाइज होते हुए संवैधानिक स्थिति सब की एक होते हुए भी शासन का सबसे बडा दोष यह है कि उनके वर्तनमानों में भिन्नता है, उनकी सेवा शर्तों में भिन्नता है। नतीजा यह है क्योंकि यह घनी आबादी वाला देश है इसलिए यहां पर एम्पलायमेंट जिस रफ्तार से मिलनी चाहिय उस रफ्तार से रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आप उनकी व्यवस्था का फायदा उठा रहे है। वे यह समझते है कि हमारी नौकरी चली जायगी तो हम कहां से खायेंगे। आज शासन अपने कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, उनका दोहन कर रहा है, उनके साथ अन्याय कर रहा है। हम यहां बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह डबल स्टैण्डर्ड है। आज भी हमारे जो सरकारी कर्मचारी है वे द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी है। उनको वोट का अधिकार है लेकिन खड़े होने का अधिकार नहीं है। सन् 1983 में इसी सदन में मैंने एक दिन की बहस इस पर कराई थी। उसमें मैंने बताया था कि किन-किन देश म सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं। वे ले सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और अगर जीत जायें तो उनक दफ्तर से जहां पर व काम करत है, उनको अवकाश मिलेगा ताकि वे एम एल ए या एम पी क रूप में काम कर सके। उसक बाद फिर व अपनी पोस्ट पर जा सकते हैं जैसे कि डेपुटेशन पर जात है। जैसे यह सरकारी कमचारी होकर के जनता की सेवा कर रहे हैं तो क्या वह एम एल ए हो कर के जब काम करने लगेंगे तो क्या व देश की सेवा नहीं कर रहे होंगे। क्या देश की सेवा करने का हक उस कर्मचारी का नहीं है क्या वह देश का नागरिक नहीं है? जब सब नागरिक है तो नागरिकता का अधिकार बराबर सबको मिलना चाहिये। आपने अपने कर्मचारियों से यह अधिकार छीन रखा है। उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना रखा है। यह आज की बात नहीं है यह सन् 1945 का जो गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट था उसी से संविधान में लकर रखा है। 42 वर्ष हो रहे हैं लेकिन हमारी सरकार के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया और जब तक संविधान में आप ऐसी व्यवस्था रखेंगे तब तक अदालत भी उसको निकाल नहीं सकती अदालत मजबूर है इन्टरप्रेट करने में Provision in the Constitution to be interpreted by the Courts; whether it is Supreme Court or the High Court. तो सुप्रीम कोट का जो उन्होंने हवाला दिया है यह बिल्कुल बेकार है। संविधान में है और संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कहेगी। अब देखिये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। उसमें मैज्योरिटी व्यू कुछ है और माइनोरिटी व्यू कुछ है। जो इसमें कहा है : "न्यायालय के बहुमत की राय के अनुसार अनुच्छेद 310(1) में निहित प्रसाद पर्यन्त सिद्धांत (अर्थात् राष्ट्रपति/राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त कोई पद धारण करना...

SHR V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): How much time would you take?

SHRI P. N. SUKUL: I am at the pleasure of the Chairman.

SHRI V. GOPALSAMY: I am not saying anything; just I wanted to know.

SHRI P. N. SUKUL: I have just told you; for these very people, I have spent five years in jail. You can very well imagine.

SHRI V. GOPALSAMY: I understand your agony. Then I also know the strategy of the Government.

SHRI P. N. SUKUL: You need not.

मैं जो पढ़ रहा था फिर से पढ़ रहा हूं ।

"न्यायालय के बहुमत की राय के अनुसार अनुच्छेद 310 (1) में निहित प्रसाद पर्यन्त सिद्धांत (अर्थात् राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त कोई पद धारण करना), अनुच्छेद 311 के खण्ड (1) और (2) द्वारा असैनिक कर्मचारियों को दिया गया संरक्षण और अनुच्छेद के खण्ड (2) के दूसरे परन्तुक द्वारा वापस लिया गया संरक्षण, सभी का लोक नीति के आधार पर और लोकहित में तथा लोक कल्याण के लिये संविधान में उपबंध किया गया है ।"

यह कोट किया। आपने संविधान में इन्हीं नामों से व्यवस्था की है और जो संविधान बनाया है वह लोक हित में बनाया गया है लोक कल्याण के लिये बनाया गया

3 00P.M. है। यह जो दण्डात्मक और अन्याय-पूर्ण व्यवस्था है, वह भी लोकहित में कही गई है, जब कि यह लोक हित के बिल-कुल अलग है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि यहां पर जब जनता पार्टी और लोक दल की सरकार आई तो उस सरकार ने भी इस बारे में नहीं सोचा । आज श्री बापू कालदाते जी यह विधेयक लाये हैं। पहले इनको सोचने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इनके तमाम मंत्रियों को करोड़ों रुपये कमाने का मौका मिला । हमारे कर्मचारियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, इस बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं । आज हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन के राइट्स नहीं हैं । दे आर वर्कर्स । एवरी वेज अर्नर इज ए वर्कर । जैसा मैंने शुरु में कहा, जिसको मजदूरी मिलती है, जो श्रम करता है, एक निर्धारित और निश्चित मजदूरी पाता है वह वर्कर है । लेकिन सरकारी अधिकारियों को अधिकार नहीं है । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन के अधिकार नहीं हैं, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं हैं, राजनैतिक अधिकार नहीं हैं । लेकिन इन स्थितियों के बावजूद हड़तालें होती हैं। आज विचित्र बात यह है कि हड़ताल का उनको राइट न होते हुए भी हर राज्य में हड़तालें होती हैं । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल करते हैं । वे इस अधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से करते हैं । आपको बाध्य होकर उनसे समझौता करना पड़ता है। लेकिन आप संविधान की किताब में इसको नहीं रखना चाहते हैं । इसी को ड्युएलिज्म कहते हैं । यही हमारी पोलिटी में इनहरेन्ट कंट्रेडिक्शन है । इस विरोधा-भास को और द्वन्द्व को जब तक आप दूर नहीं करेंगे तब तक प्रशासन जिस तरह का होना चाहिए वह नहीं हो सकता है । अगर हमारे कर्मचारी असंतुष्ट हैं तो जो काम हम उनसे लेना चाहते हैं वह नहीं ले सकते हैं । हमारा वेतन आयोग वेतनों में पेरिटी को न माने और जिसको ज्यादा वेतन मिलना चाहिए उसको कम मिले और जिसको कम मिलना चाहिए उसको ज्यादा मिले तो पेरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और जो सम्बद्ध वर्ग हैं उनमें असंतोष व्याप्त हो जाएगा । इसका परिणाम यह होगा कि कर्मचारियों में द्वेष पैदा हो जाएगा और यह द्वेष की भावना उनके कार्यों में प्रतिबिम्बित होगी । आज हमारे देश को आजाद हुए 40 वर्ष हो चुके हैं । लेकिन अभी तक हमारी कोई राष्ट्रीय वेतन नीति नहीं बनी है । चालीस वर्षों के बाद भी हम आवश्यकताओं के आधार पर न्यूनतम वेतन नहीं दे पाये हैं । बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली आदि शहरों में नीड बेस्ट जो मिनिमम वेज होना चाहिए, वह अभी तक हम नहीं दे पाये हैं । अधिकतम

[श्री पशुपति नाथ सुकुल]

वेतन की बात में नहीं कर रहा हूं। मैं नीड वेस्ट मिनिमम की बात कर रहा हूं। अगर कर्मचारियों को वह भी नहीं मिलेगा तो फिर वे क्या करेंगे ? वे कोई पार्ट टाइम जोब करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। आज हमने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं जिनमें कर्मचारी भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर होते हैं। आपने एन्टी करप्शन एक्ट बनाया है। हर पार्टी करप्शन हटाने की बात करती है। लेकिन फिर भी समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्यों स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है ? हमारे ढांचे में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इसका एक कारण यह है कि हम अभी तक कालोनियल सिस्टम को बनाये हुए हैं। जिस ढांचे को हम गालियां दिया करते थे, जिन अंग्रजों को हम गालियां दिया करते थे, हम उसी ढांचे को बनाए हुए हैं। अगर कर्मचारियों में संतोष की भावना नहीं होगी तो अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में सरकार लार्जेस्ट इम्प्लायर है। सरकार से बड़ा इम्प्लायर इस देश में कोई नहीं है। अगर सरकार अपने कर्मचारियों को न्याय नहीं देगी, उनको आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनैतिक न्याय नहीं देगी तो वह एक मोडल इम्प्लायर कैसे कही जाएगी ? तो सरकार अगर माडर्न एम्प्लायर नहीं बनती तो वह फैक्टरियों के ओनर्स से कैसे अपेक्षा करती है, मिल मिलिकों से कैसे अपेक्षा करती है कि वे माडर्न इम्प्लायर्र बने। इसके लिये सरकार को स्वयं ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी होंगी। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक आप अपने कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कर्मचारी नौकरी करने के लिये काम तो कर देगा लेकिन उसका जो अपनी सरकार में विश्वास होना चाहिए, जो आस्था होनी चाहिए वह आस्था पैदा नहीं होगी। इसीलिये मैं आपसे कहता हूं और जैसे हमारे बापू कालदाते जी ने इसमें सुझाव दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड 2 और खंड 3 जो हैं उसको डिलिट किया जाय, इनका लोप होना चाहिए। अगर हमें किसी सरकारी कर्मचारी को दंडित करना है तो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत नियमों के आधार पर सरकार को जाना चाहिए। जब तक आप एसा नहीं करते हैं तब तक आप अच्छे मालिक नहीं चहलायेंगे। जैसा मैंने कहा कि आप अपना एक नीड बेस्ड मिनिमम वेज निर्धारित कीजिये और अपनी एक राष्ट्रीय वतन नीति की घोषणा कीजिये और स्टेट इम्प्लाईज, राज्य सरकारी के बीच में, जिसमें केन्द्रीय कर्मचारी भी शामिल हैं, उनके वेतन मानों, भत्तों, सेवा संबधी नियमों में जो असमानताय हैं उनको आप समाप्त कीजिये। यह कहकर आप मुक्त न हों कि यह उड़ीसा सरकार का मामला है, उड़ीसा सरकार उनको देगी। देश की सरकार आप हैं, संविधान आप बनाते हैं; उड़ीसा की सरकार नहीं बनाती है। इसलिये आप संविधान में संशोधन करके इसको बदल सकते हैं। आपके बनाये हुए जो नियम हैं उन नियमों के अंदर ही उड़ीसा सरकार बाध्य है। आज जो आर्थिक विषमतायें हैं उनका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। तो हमारे देश की जो सरकार है, केन्द्रीय सरकार, उसका यह परम पावन कर्त्तव्य है कि वह देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हैं और जो राज्यों के कमचारी हैं उनके बीच में जो आर्थिक विषमतायें हैं उनको दूर करे और उनको एक स्तर पर ले जाय तभी उन्हें संविधान में समुचित आस्था होगी और तभी वह समुचित ढंग से राज्य की सेवा कर पायगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डा० बापू कालदाते जी का जो विधेयक है इसका हार्दिक स्वागत करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Yes, Mr. Vijaya Mohan Reddy.

DR. BAPU KALDATE (Maharashtra): Sir, May I read out rule 118 which relates to withdrawal of a Bill? It reads:

> "The member in charge of a Bill may at any stage of the Bill move for leave to withdraw the Bill, and if such leave is granted, no further motion shall be made wih reference to the Bill."

Sir, I am just requesting... (*Interruptions*).

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: This is very dangerous.

डा० बापू कालदाते : उपसभाध्यक्ष महोदय, रूल 118 के तहत मैं कह रहा हूं । मैं सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान करें ।

... (**व्यवधान**)

SHRI P. N. SUKUL: Mr. Kaldate, you are withdrawing at the instance of Shri Gopalsamy.

... (**व्यवधान**)

श्री धूलेश्वर मीणा (राजस्थान) : आप इतना बढ़िया बिल लाये हैं, इस पर बहस करने दीजिये ।

SHRI V. GOPALSAMY: When the Government is playing such dirty tricks...

डा० बापू कालदाते : मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं । (**व्यवधान**)... मैं यह बात यहां पर इसलिये लाया हूं कि ये विधेयक सदन में पहले भी दो तीन घंटे तक चला और अभी भी चला है । दूसरी बात यह है कि many of the Private Members' Bills on the very same type of subject are already pending with us. (*Interruptions*).

मैं यह चाहता हूं कि इसको मुझे वापस लेने की अनुमति दी जाये । इसके ऊपर जो भी हमारे मित्र... (**व्यवधान**)

श्री पशुपति नाथ सुकुल : आप नहीं रोक सकते हैं ।

डा० बापू कालदाते : मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसकी इजाजत दें । ... (**व्यवधान**)... आप मत दीजिये । इसके बारे में बहुत से सम्मानित सदस्यों की इच्छा है कि वे इस पर अपने विचार प्रकट करें और वे भी इसमें भाग लेना चाहते हैं । मैंने जब विधेयक पेश किया था तो मैं चाहता था कि इस मामले पर अच्छी बहस हो जैसे कि हमारे सम्मानित सदस्य सुकुल जी, हैं सभी की भावनाएं इसके उपर आ जाएगी तो हो सकता है यह सरकार पुनर्विचार कर के और खुद यह कह कर सामने आएगी कि हम इसको डिलीट करने का प्रयास करेंगे लेकिन मुझे यह लगता हैं कि आज के समय और भी कुछ मित्रों के विधेयक हैं और भी कई माननीय सदस्यों की इन में भाग लेने की इच्छा है इसलिए मैं चाहता हूं कि आज मुझे सदन इस को वापिस लेने की इजाजत दे और जो अन्य विधेयक आएगे उन पर माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा सुविधा मिलेगी और वे भी विधेयक के बारे में विस्तार से चर्चा करें। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह अनुमति मांगता हूं कि मुझे इस विधेयक को वापिस लेने की इजाजत दें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I have gone through Rule 118 which has been referred to by Dr. Bapu Kaldate. I have gone into the procedure also. The rule is very clear. "The member in charge of a Bill may at any stage of the Bill move for leave to withdraw the Bill..."

SHRI P. N. SUKUL: He is not withdrawing the Bill. He says for today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): No, no, he is withdrawing.

DR. BAPU KALDATE: I am moving for leave to withdraw it. Not for today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Sukul, he is seeking leave of the House to withdraw the Bill. Mr. Narayanasamy, why don't you wait? Actually the rule is very clear. It is not "at any time"; it is "at any stage". Now the stage is, it is in the middle of a stage; the consideration of the Bill is in the middle of the stage. When this stage is over, the Member has got that right which is there under Rule 118. (*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY: Even during discussion he can withdraw.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Not "during" the discussion, but after the "completion" of the stage.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): Only 'after' the discussion is over.

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): What is the ruling?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The discussion will continue.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): I am on a point of order.

SHRI V. GOPALSAMY: I am on a point of order. A member who has moved the Bill can withdraw it at any stage. Now here when a discussion on a Private Member's Bill is taking place, even during the discussion, he can withdraw it. "At any stage" means at any time—even during a discussion. That is why he has moved to withdraw this Bill. Mr. Vice-Chairman, Sir, why has the ruling party suddenly fielded 8 speakers this time? The reason is very simple. My Bill is the next Bill, which is about the Postal Bill. (*Interruptions*) Yes, Sir, that is the reason.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): That is not the reason, but because there are speakers who want to speak on this Bill.

SHRI V. GOPALSAMY: The Government is very touchy, the Government is very nervous.

SHRI M. M. JACOB: That is casting aspersions on the ruling party.

SHRI V. GOPALSAMY: They want to see that that is not taken up. That is why suddenly...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please Mr. Gopalsamy, this is a Private Members' day. If any Member wants to speak on that, how does Government come into the picture? Why do you bring in the Government? If the private Members want to participate in the discussion on a Private Member's Bill, how can the Government come into the picture? "This is your private Members' time. Let us not bring the Government into this. When a thing goes on record, we will have to be careful.

SHRI V. GOPALSAMY: This is happening under the very nose of the House. They want not to take up that Bill. That is the Postal Bill which I have introduced. That will be taken up for consideration immediately after this. That is why they have fielded seven or eight speakers. Because they do not want to discuss anything about the Postal Bill. I know it. That is why....

SHRI M. M. JACOB: In that case we could have opposed it at the introduction stage itself.

SHRI V. GOPALSAMY: Government is not prepared for a discussion on the Postal Bill. They are touchy and nervous because the President has not given assent to that Bill. My Bill is the next. So suddenly they have fielded eight speakers.

SHRI SANTOSH MOHAN DEV: It should not go on record. (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I have already told you... (*Interruptions*)... One minute, please. If that was the intention of the Government...

SHRI V. GOPALSAMY: You can silence the voice of democracy....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Let us not read in between the lines.

(*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY: The people will teach you a lesson... (*Interruptions*)...you will be thrown into the dust-bin as in Kerala and West Bengal. The people of India will teach you a lesson... (*Interruptions*)...

THAKUR JAGATPAL SINGH (Madhya Pradesh): In the last elections we taught you a lesson. In the last General Elections you were nowhere, my friend... (*Interruptions*)...

SHRI CHITTA BASU: Mr. Vice-Chairman, Sir, the Member in charge of this particular Bill wants to move for the leave of the House to withdraw his Bill, and that is under rule 118.

SHRI P. N. SUKUL: And leave is not granted... (*Interruptions*)...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: That stage has not yet come.

SHRI CHITTA BASU: You are bound by the rules and the rule is very specific. You have been advised that "stage" means the stage of consideration, as I understood it. Sir, if you are pleased to look into the subsequent proviso of this rule 118, the leave for withdrawal of the Bill can also be moved when the Bill is also at the second stage, that is, at the select committee stage. This is at the consideration stage. Consideration stage does not mean that during the discussion, at any point of discussion, there cannot be any withdrawal motion or closure motion. Sir, I can also move a closure motion. Do you take the plea that the consideration stage should be continued and completed and there should be a closure motion after that consideration stage of the Bill is over? It is too far extended a logic. Sir, I do not like to take much of your time. You are quite an informed person. Therefore, "stage" here does not mean, I say, the stage of consideration. "Stage" here means "at any point of time." Therefore this honourable Member has got the right to move under this rule to withdraw his Bill at any point of time, at any stage of consideration. Now, the introduction stage does not arise for the Bill. There is the consideration stage, the select committee stage and again consideration stage and, again, what you call, the third reading, is there. Do you mean to say that during the pendency of the discussion I have not got the right to move for closure? I enjoy the right to move for closure. Therefore he is also entitled to move a motion seeking leave for the withdrawal of the Bill. Under the rule you cannot prevent it. They are there not to give the consent or leave for withdrawal. It is for the House.

Sir, another point is very relevant in this context. How long will you prevent the Members of the House...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): That does not come under the point of order. ... (*Interruptions*)...

SHRI CHITTA BASU: ..... by way of majority to stall such an important Bill which is introduced by a Member? This strategy will not help you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You cannot raise it under the guise of a point of order.

SHRI CHITTA BASU: I think there is need of allowing private Members to introduce a Bill. Because you are in the majority, because you can at any stage, at any point of time, prevent the minority Members of the House, who have got the privilege of introducing a private Member's Bill, you can stall it, you can kill it. I condemn the attitude of killing a Bill of this important nature, for which the President has not given his assent.

SHRI V. GOPALSAMY: What prompted Mr. Jacob to convince all the Members to give their names? You are particular to see that my postal Bill is not taken up.

SHRI P. N. SUKUL: This Bill is equally important.

THAKUR JAGATPAL SINGH: This is a question of all-India services.

SHRI CHITTA BASU: Why are you angry? (*Interruptions*)

PROF. C. LAKSHMANNA: Mr. Vice-Chairman, Sir, the rule is...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I have given the floor to Prof. Lakshmanna. Let there be no interruptions.

SHRI CHITTA BASU: Your Bill will be half discussed this way.

PROF. C. LAKSHMANNA: Mr. Vice-Chairman it says, "at any stage." "Any" means "all stages". Then what is a stage? The dictionary meaning, I will quote for you:

"The point reached in, or a section of life, development or any process."

SHRI V. GOPALSAMY: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): No interruptions please.

SHRI M. M. JACOB: This should be expunged from the proceedings, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): This will not go on record. Only Prof. Lakshmanna will go on record; no other Member.

PROF. C. LAKSHMANNA: I quoted from the dictionary the meaning of "stage". (*Interruptions*) Can't you even listen to this? If you do not listen to it, what can I do? I have read it from the dictionary. Do you want me to read once again? You please listen to it:

"A point reached in, or a section of, life, development and any process."

Now there is a process of discussion of this particular Bill. In this process there are three or four stages. The first stage is the introduction stage. The second stage is the discussion stage. The third stage is the acceptance or the rejection stage. The Member who has introduced the Bill, is having the right to withdraw the Bill at any one of these three stages. He may give a notice at the request of the House, or at the request of another Member he may withdraw it. Or when it is under discussion he can withdraw. After the discussion, when it is to be put to vote at the request of either the Government or of the Members or anybody, it can again be withdrawn. In this particular case the Member

*Not recorded.

is exercising his option, because all the stages are allowed, at the stage of discussion itself for the reasons best known to him. It is his prerogative to introduce. It is his prerogative to press for its withdrawal. But it is the prerogative of the House whether to accept it or not. I am not going into that. Therefore, on that basis he has been asking for the withdrawal. To say that at a stage when there is a discussion the discussion should continue, is not a valid point. Therefore, all that, Mr. Vice-Chairman, you can do is to ask the House for its opinion. And if in the opinion of the House the discussion should continue, let it continue. I am not questioning that. But you cannot deny that opportunity to the Member to exercise his right, you cannot do away with his right. The Member is having the right to introduce. The Member is having the right to press for it. The Member is having the right to ask for a discussion. This provision is important. Therefore, all that you can do is to seek the opinion of the House whether he has the permission to withdraw the Bill at this stage, at the stage of discussion or not. Therefore, I request you kindly to exercise that option and give him the right to use his own...

SHRI P. N. SUKUL: I am on a point of order. The provision in Rule 118 is very clear. You read its second proviso. It says:

"Provided further that where a Bill has originated in the House and is pending before the Council, the member in charge shall move a motion in the Council recommending to the House that the House do agree to leave being granted by the Council to withdraw the Bill and after the motion is adopted..."

That motion has not been adopted.

PROF. C. LAKSHMANNA: Nobody disputed it. Then again you have to move.

SHRI P. N. SUKUL: "After that motion is adopted by the Council and concurred in by the House, the member in charge shall move for leave to withdraw the Bill."

PROF. C. LAKSHMANNA: But it has not taken away the right.

SHRI P. N. SUKUL: Now it means that he has moved the motion. So, now it is for the House.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह हैं कि इस सदन में एक परिपाटी है कि जो प्राइवेट मैम्बर्ज बिल हैं, इनमें सत्ता पक्ष के लोग भी हो सकते हैं और विरोध पक्ष के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जिस वक्त हम अपने विधेयक को प्रस्तुत करते हैं उस समय सदन की एक परिपाटी हैं कि सारा सदन एक ध्वनि से उस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देता हैं। इस लिए मेरा यह निवेदन हैं कि उसी सिद्धांत को मानते हुए जबकि डा० बापू कालदाते का यह विधेयक था और उस पर चर्चा हो रही थी तथा उन्होंने अनुमति मांगी है कि इस विधेयक को विदड्रा करने की अनुमति दी जाए तो उसी परिपाटी को मानते हुए मैं सारे सदन से अनुरोध करूंगा कि डा० बापू कालदाते का जो सुझाव हैं या इन्होंने जो विधेयक मूव किया हैं इसको विदड्रा करने के लिए सारा सदन ध्वनिमत से मंजूरी दे।

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Bhagat, the trouble-shooter, came here to request... not to allow...

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI ARJUN SINGH): Sir, this is too much. I think Mr. Gopalsamy, the hon. Member will also realise that he is entitled to his views, but to cast aspersion on everybody else just to support his views is not correct.

SRHI V. GOPALSAMY: Did I say any unparliamentary word?

SHRI M. M. JACOB: I appreciate what Prof. Lakshmanna has said on Rule 118. We are not against his viewpoint. He has every right to express his viewpoint and we are ready to listen to all the viewpoints. But the hon. Member himself has said about various stages. He was kind enough to read the meaning of the word 'stage'. First stage of introduction was there and he could have withdrawn it. Then there was the second stage, when you take up the Bill for consideration. That was another stage. There again it could have been withdrawn. Then there is another stage after the speeches. In between speeches and talks you cannot withdraw arbitrarily. You can withdraw even after these. There are four stages you have mentioned in the dictionary. In all the stages you are permitted to withdraw. But how can you withdraw in between a stage? It is inside the stage. So, I do not think this is a stage. So, I think it cannot be withdrawn.

PROF. C. LAKSHMANNA: Being a professor of English, I know what is meant by 'stage'.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Being a professor in English is a different from being a politician. Let us not go by the professor of English.

The hon. Members have raised a point that the Member has a right. He has a right to move for leave of the House to withdraw the Bill. There are very clear rules in the Rules of Procedure and Conduct of Business regarding the stages. If the member is free to withdraw the Bill at any time of its consideration or discussion, there are other provisions in the same Rules of Business where it is mentioned 'at any time. But here, particularly a stage is fixed—at any stage of the Bill. The stages you yourself concede—at the stage of introduction, at the stage of consideration, at the stage of rejection or acceptance. If that was the intention of the rule-makers they could have used it at any stage as was used in other clauses. The discussion will continue. It cannot be withdrawn.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw your attention to rule 119 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, and I quote:

> "If a motion for leave to withdraw a Bill is opposed, the Chairman may, if he thinks fit, permit the member who moves and the member who opposes the motion to make brief explanatory statements and may thereafter without further debate, put the question."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): It is not opposed. I am only giving the ruling on the point of order. After this stage he has got still right to ask the leave of the House to withdraw. Now, Dr. G. Vijaya Mohan Reddy.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I appreciate the spirit behind the Constitution (Amendment) Bill, 1985, brought forward by my hon. friend, Dr. Bapu Kaldate for discussion through private Members' Bill. It is a very very important Bill. I support all the objectives contained in this Bill. I suggest one amendment in article 311. Clause 2 (b) and (c) and Clause 3 may be deleted. Thank you.

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, इसका संबंध देश के लाखों शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों से है और जिस माननीय सदस्य ने इसे प्रस्तुत किया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन कर्मचारियों और अधिकारियों की फिक्र की, उनकी ओर उनका ध्यान गया और उनकी एक अहम महत्वपूर्ण समस्या के सम्बन्ध में यह बिल प्रस्तुत किया ।

मेरे सदन के सभी मित्र जानते हैं कि मैं स्वयं शासकीय सेवा में 18–19 वर्ष कार्यरत रहा, इसलिए यह विषय मुझे बहुत प्रिय है... (व्यवधान)...

SHRI V.. GOPALSAMY: How many speakers are there still?

AN HON. MEMBER: Twenty Members... (*interruptions*).

SHRI AJIT P. K. JOGI: I have your permission to speak now. इसलिए यह एक ऐसा विषय है, जो मुझे बहुत प्रिय है। इसके पहले कि हम इस बिल के गुण-दोषों पर विचार करें, मैं माननीय सदन का ध्यान इसकी एतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर ले जाना चाहूंगा। जो शासकीय ढांचा आज राष्ट्र में विद्यमान हूं, वह ढांचा हमें हमारे पूर्ववर्ती शासक ब्रिटिश के द्वारा दिया गया और वह लंदन में बैठकर, हमारे देश से दूर बैठकर एक ऐसे समय में जब कि संचार के साधन बहुत दक्ष नहीं थे, तब इस राष्ट्र में राज्य करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जिस ढांचे की संरचना की... (व्यवधान)...

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Jacob is going there.

SHRI ARJUN SINGH: Now are you going to intercept our talk also?

PROF. C. LAKSHMANNA: That is only your prerogative.

SHRI ARJUN SINGH: I think that only shows his inclination.

PROF. C. LAKSHMANNA: It has already been proved.

SHRI V. GOPALSAMY: Sorry I have disturbed you.

PROF. C. LAKSHMANNA: Does not matter, he will take his own time.

SHRI AJIT P. K. JOGI: If you go on interrupting, I am bound to take longer.

इसलिए जिस ढांचे की संरचना ब्रिटिश शासकों ने इस राष्ट्र में की वह ढांचा एक ऐसा ढांचा है जिसकी तुलना का ढांचा किसी राष्ट्र में, किसी देश में देखने को नहीं मिलता। यह ऐसा ढांचा हैं जो कि बहुत मजबूत है। यह ऐसा ढांचा हैं जो अपने आप में स्वतंत्र है। यह ऐसा ढांचा हैं जो अपने आप निर्णय लेकर उनका कार्यान्वयन करने की क्षमता रखता हैं। यह ऐसा ढांचा है जिसे इस दृष्टिकोण से बनाया गया था कि उसे यदि शासन की नीतियां बता दी जाएं तो वह अपने विधेयक का प्रयोग करके उन नीतियों का कार्यान्वयन कर सकता हैं। इस उद्देश्य से एक बहुत ही मजबूत ढांचा शासन तंत्र का राष्ट्र को दिया गया और यह एक विचारणीय बात है कि विश्व के किसी भी राष्ट्र में सिविल सर्विस प्रशासन तंत्र इतना मजबूत नहीं हैं, इतना ताकतवर नहीं है। यहां तक कि इंगलैंड जिन्होंने यह ढांचा हमें बनाकर दिया उनका जो प्रशासन तंत्र है, जो नौकरशाही हैं, वह भी अपने आप में इतनी मजबूत नहीं हैं। वहां जिला स्तर पर, कलेक्टर का कोई पर्याय नहीं है। संभाग के स्तर पर कमिश्नर का कोई पर्याय नहीं हैं। इसी तरह से मजबूत और ताकतवर नौकरशाही का पर्याय इंगलैंड में भी नहीं है। अमरीका और फ्रांस और अन्य देशों के प्रशासन तंत्र की अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि कोई भी प्रशासन तंत्र ऐसा नहीं है जो इतना मजबूत हो, जहां की नौकरशाही इतनी मजबूती से बंधी हो। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए मैं कहना, चाहता हू कि जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद इस राष्ट्र में कैसी भावनाए थीं, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। जैसे ही आजादी मिली, हमारे नेता जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था, जिन्होंने आजादी दिलाने के लिए मेहनत की थी, उनके सामने एक अत्यंत ही विलष्ट परिस्थिति उत्पन्न हुई जन प्रतिनिधियों का यह कहना था कि जिस ढांचे ने हमारा शोषण किया हैं, जिन लोगों ने हमें स्वतंत्रता संग्राम की अवधि में पकड़कर जेलों के सींकचों में रखा, जिन लोगों ने हम पर अत्याचार

[श्री अजीत जोगी]

किए, ऐसे ढांचे को बनाकर नहीं रखना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि यह ढांचा अपने आप में बहुत मजबूत है और यह जन प्रतिनिधियों को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने नहीं देगा। इसलिए इसमें आमूल परिवर्तन कर देना चाहिए। जो लोग यह बात कर रहे थे उनके समर्थन में बहुत बड़ी आवाज़ राष्ट्र में थी। जब संविधान बन रहा था, कांस्ट्रीटयूयेंट ऐसेम्बली में हमारे विद वतजन सम्मिलित होकर संविधान बन.ने पर विच.र कर रहे थे, जो उस समय वाद विवाद हुआ, वह भी बड़ा रुचिकर हैं और उनमें भी हमें दो प्रकार की भावना इस प्रशासन तंत्र के बारे में देखने को मिलती है। कुछ लोगों ने कहा कि इस प्रशासन तंत्र को बिलकुल समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह प्रशासन तंत्र गुलामी का प्रतीक है, यह प्रशासन तंत्र ऐसे लोगों ने भरा हुआ है जिन्होंने आजादी से पहले सघर्ष करने वाले लोगों का विरोध किया था, उन्हें ले जाकर जेलों में भेजा था, उन्हें सजा दी थी। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे जो इससे सहमत नहीं थे और उनका यह कहना था कि राष्ट्र की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसे ऐसे ही मजबूत प्रशासन तंत्र की आवश्यकता है। बहुत अधिक वाद-विवाद के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डा० अम्बेदकर इन तीनों प्रमुख व्यक्तियों ने यह बात बार बार कही कि हमें देश की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे प्रशासन तंत्र की आवश्कता है। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय राष्ट्र ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी स्थितियों से हो कर गुजर रहा था उसी समय हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा हुआ और बटवारे को लेकर देश की कानून और व्यवस्था की परिस्थितियां छिन्न-भिन्न हुई थीं, खून हुआ था, हत्याएं हुई थीं, हमले हुए थे और ऐसे समय में एक मजबूत शासनतंत्र की आवश्यकता थी। नेहरू जी, सरदार पटेल और डा० अम्बेदकर यह चाहते थे कि ऐसा प्रशासनतंत्र बना रहे। उनका यह भी कहना था कि जिन लोगों के हाथ में तब सत्ता आयी थी, जो हमारे जनप्रतिनिधि तब थे उनमें से बहुत से लोगों ने, अधिकांशतः लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। वे आजादी की लड़ाई में भागी होने के कारण अपनी व्यक्तिगत शिक्षा की ओर, अपने आप को प्रशासन के प्रति शिक्षित करने की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाये। इसलिए वे लोग बिना ऐसे प्रशासनतंत्र के इस राष्ट्र में शासन चलाने को सक्षम नहीं थे। जिन लोगों को पहले से हमारे ब्रिटिश शासकों ने इस राष्ट्र में शासन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी उन परिस्थितियों में हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे विद्वान कानूनवेत्ताओं ने मिल करके संविधान में ऐसे ही प्रशासनतंत्र को रखे जाने का प्रावधान किया था और उसी से सम्बन्धित यह अनुच्छेद 311 है जिस पर सम्मामित सदस्य डा० बापू कालदाते जी ने यह संशोधन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है।

जैसा मैं कह रहा था हमारे राष्ट्र के प्रशासनतंत्र में हमारी नौकरशाही अपने आप में विशिष्ट है। विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां इस प्रकार का प्रशासनतंत्र हो। जिस प्रकार हमारे राष्ट्र में जिलों में जिलाध्यक्ष का कार्यालय होता है वैसे यूनाइटेड किंगडम में एम० पीज का, संसद सदस्यों का कार्यालय होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में यहां तक कि जो पुलिस का तंत्र है वह भी चुने हुए लोगों के अधीन होता है। इसी प्रकार हमारे प्रशासनतंत्र और अन्य राष्ट्रों के प्रशासनतंत्रों में बहुत बड़ा अन्तर है। प्रशासनतंत्र में नौकरशाही कई सिद्धांतों के आधार पर बढ़ती आई है और उनमें से दो प्रमुख सिद्धांत जो हैं वे यह हैं–प्रिंसिपल आफ एनानिमिटी और प्रिंसिपल आफ न्यूट्रालिटी आफ सिविल सर्वेन्ट। अर्थात नौकरशाह जो है वह किसी राजनीतिक पक्ष का पक्षधार नहीं होता और दूसरी बात नौकरशाह का अपनी साक्षरता का चेहरा नहीं होता वह अपने राजनीतिक नेताओं और राजनीति में काम करने वालों के चेहरे के पीछे कार्य करता है। वे जो नीति बनाते हैं उनका क्रियान्वय

करता है। इन दो सिद्धांतों को बनाये रखने के लिए ही संविधान में अनुच्छेद 311 की व्यवस्था की गयी है। यह सोचा गया। जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया वे इस आकलन पर पहुंचे कि यदि हमें अपने प्रशासनतंत्र को इसी प्रकार निष्पक्ष रखना है, इसी प्रकार परदे के पीछे रख कर क्रियान्वयन की सीमा तक सीमित रखना है तो हमें उन्हें कुछ न कुछ संरक्षण देना होगा जिसके आधार पर वे निष्पक्ष रह सकें, जिसके आधार पर वे संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रख कर अपने कार्य का सम्पादन कर सकें। और इसी-लिए अनुच्छेद 311 में यह प्रावधान किया गया था कि अन्य राष्ट्रों की तरह यहां के नौकरशाहों को उनके अधि-कारियों को उनकी सरकार बिना निश्चित प्रक्रिया का पालन किये, बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के माने हुए उनको किसी भी प्रकार का दण्ड न दे सके। उन्हें निर्भीक बनाना आवश्यक था। वे निर्भीक रह-कर ही उस ढांचे में जिस ढांचे के वे अंग बनाये गये हैं, अपने कार्य का सम्पादन कर सकते थे और इसी विशिष्ट उद्देश्य को समक्ष रखकर अनुच्छेद 311 का प्रावधान संविधान में किया गया था।

एक विशिष्ट बात जो हमारे प्रशासन तंत्र के विषय में हमें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए वह है कि हमारा प्रशासन तंत्र स्थायी है। राजनैतिक सरकार आती है और चली जाती है। जनादेश के आधार पर राजनैतिक शासन आता है और शासन करता है। जब तक उसको जना-देश प्राप्त होता है तब तक वह शासन करता है। उसके बाद जब दूसरा जनादेश मिलता है तो उस जनाधार पर वह शासन करता है और फिर चला जाता है। लेकिन नौकरशाह जो प्रशासन तंत्र का स्थायी अंग है वह इस राष्ट्र की व्यवस्था को स्थायी रखने के लिए बना रहता है। यदि इस राष्ट्र में सबसे अधिक किसी ने अपना योगदान दिया हैं। तो वह इस राष्ट्र का प्रशासनतंत्र है। वे लाखों-करोड़ों अधिकारी और कर्मचारी हैं वे स्थायी रूप से बने रहते हैं। वे अपने कार्य का निष्पादन करते रहते हैं, अपने कार्य का सम्पादन करते रहते हैं। इसलिए जब भी हम अपने राष्ट्र के प्रशासनतंत्र के लोगों की चर्चा करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जहां एक ओर राजनेता अस्थायी है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनतंत्र स्थायी है और इस प्रशासनतंत्र ने अपने स्थायित्व का लाभ उठाकर इस राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है। इसलिए इस प्रशासनतंत्र को एक निश्चित सीमा में कार्य करने की स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। राजनेता और प्रशासन के अलग-अलग कार्य क्षेत्र हैं। संविधान में राजनेता का कार्य कानून बनाना है और नीति निर्धारित करना है। वह उद्देश्य और लक्ष्य तय कर दे और उसके बाद नौकर-शाह का कार्य होता है कि वह उस नीति को कार्यान्वित करे, उस नीति का पालन करे। इस तरह से दोनों की भूमिका अलग-अलग है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रशासनतंत्र हमारे नौकरशाह उनकी जो भूमिका संविधान में तय की गई है जो भूमिका कानून में तय की गई है उसका सही अर्थ में पालन करे तो हमें उन्हें अपने कार्य को कार्यान्वित करने के लिए पूरी स्वतन्त्रता देनी होगी। यह स्वतन्त्रता तभी दी जा सकती है जब हम प्रशासन को ऐसा आश्वासन अपने संविधान में दें, कानून में दें कि यदि वह अपने कार्य का पालन कानून की सीमाओं में करेंगे, यदि वे अपने कार्य का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे, यदि वे अप कार्य का सम्पादन उन मर्यादाओं की सीमाओं रह कर करेंगे जिनको राजनेताओं ने तय किया है तो उस पर किसी प्रकार का आघात नहीं हो सकता है उनको किसी प्रकार से दण्डित नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि संविधान के पूरे अध्याय में ऐसे विभिन्न प्रावधान किये गये हैं, अनुच्छेद 108, 109, 110, 111, 112 रखे गये हैं। जो यह आश्वासन देते हैं, संविधान बनाने वाले हमारे पूर्वजों की ओर से आश्वासन देते हैं कि यदि तुम अपना काम ठीक से करोगे, यदि तुम अपना काम निष्पक्ष होकर करोगे, यदि तुम अपने काम को उचित ढंग से करोगे, यदि तुम अपना काम

[श्री अजीत जोगी]

संविधान के प्रति अपनी आस्था को बनाकर करोगे तो तुम्हें हानि नहीं होगी और इसी प्रकार का आश्वासन नौकरशाही को दिया जाना, प्रशासन तंत्र को दिया जाना बहुत आवश्यक है। हम यहां इस माननीय सदन में हमेशा न्याय की बात करते हैं, न्याय के सिद्धान्तों की बात करते हैं और सबसे पहला न्याय का सिद्धान्त प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्तों है नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है। ला आफ नेचरल जस्टिस यह कहता है रूल आफ ला यह कहता है कि किसी व्यक्ति को दंड दिये जाने से पूर्व, सजा देने से पहले उसका पक्ष सुना जाना चाहिये . . . (व्यवधान) . . .

महोदय, मैं यह कह रहा था कि हम सब न्याय के सिद्धान्त की बात करते हैं और प्राकृतिक न्याय, न्याय का सबसे पहला सिद्धान्त है। प्राकृतिक न्याय यह कहता है कि किसी व्यक्ति को सजा देने के पहले दंड देने के पहले उसको सुना जाना चाहिये उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये और बिना उसके पक्ष को सुने उसे अपना पक्ष रखने के अवसर को दिये बिना उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए। जब प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त यह कहता है कि तो प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धान्त प्रशासन तंत्र के जो हमारे अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उन पर भी लागू होना चाहिये। उनको कोई दंड देने के पहले, उन्हें कोई सजा सुनाने के पहले अपना पूरा पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिये। यदि यह अवसर उन्हें नहीं दिया गया तो हम उन्हें न केवल न्याय उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं बल्कि न्याय का जो मूलभूत हिस्सा है प्राकृतिक न्याय का, नैसर्गिक न्याय का यह भी उन्हें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हम यहां इसलिए नहीं हैं कि हम समाज के एक वर्ग को न्याय से वंचित कर दें। हम उन्हें यदि न्याय दिलाना चाहते हैं तो यह तभी दिलाया जा सकता है जब कि संविधान में जो आश्वासन दिए गए हैं उसमें जो गारंटी उन्हें दी गई है उसको बरकरार रखा जाये। उस गारंटी को . . . (व्यवधान) . . . उस आश्वासन को हटाकर हम अपने प्रशासन तंत्र के इन लाखों लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे उनके साथ अन्याय ही करेंगे। हमारे सभी माननीय सदस्य जिनमें हमारे माननीय मित्र गोपालसामी भी सम्मिलित हैं वे समाज के सब वर्गों को न्याय दिलाने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ता तो यहां तक कह रहे थे कि हम अपने नौकरशाही के लोगों को मूल नागरिक अधिकारों से वंचित करते हैं। वे राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहे थे मैं उसकी संक्षेप में पुनरावृत्ति करते हुये कहना चाहूंगा कि आज का हमारा प्रशासन-तंत्र आज के हमारे नौकरशाह कानून के नियमों के अन्तर्गत जकड़े हुये हैं। उन्हें उस तरह की आम आजादी उस तरह की सुविधाएं उस तरह की स्वतन्त्रता नहीं है जो आम रूप से एक सड़क पर चलते हुये नागरिक को भी उपलब्ध होती हैं। इसलिए जब हम संविधान के इस प्रावधान इस अनुच्छेद के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने समक्ष एक ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिये जिसको चारों तरफ से नियमों से कानून से विधि से घेर कर रखा गया है जो अपने पक्ष में अपने बचाव में मूल रूप से आम रूप से सामने नहीं आ सकता जो अपना बचाव नहीं कर सकता। इसलिए हम सबका कर्तव्य हो जाता है हम जो कानून बनाते हैं हम जो विधि का निर्माण करते हैं हम सब ऐसे मूक व्यक्ति को ऐसे बचावहीन व्यक्ति को ऐसा प्रावधान दे कर संविधान के अन्तर्गत, कानून के अन्तर्गत ऐसा आश्वस्त करें कि यदि वह अपना कार्य ठीक से कर रहा है यदि वह निष्ठावान है यदि वह परिश्रमी है यदि वह कानून का पालन कर रहा है तो उस पर किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। एक बात बहुधा हम अपनी चर्चा में करते हैं। वह बात यह है कि जब हम यह आकलन करना चाहते हैं कि हमारी नीतियों का पालन सही क्यों नहीं हुआ, हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही क्यों नहीं हुआ तो हम राजनेता सदैव यह कहने लगते हैं कि हमारी नौकरशाही इतनी निष्क्रिय है इतनी अक्षम है इतनी अदत है, कि उसके कारण हम अपने लक्ष्यों को उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस तथ्य में इस आरोप में मेरा स्वतः का विचार है बहुत अधिक सार है बहुत अधिक आधार है। यह सही

है कि हमारी आशाओं, आकांक्षाओं हमारे विश्वास के अनुरूप इस राष्ट्र की नौकरशाही नहीं आई और यदि ऐसा है तो हमें उन कारणों का पता लगाना चाहिये कि क्या हमारी नौकरशाही क्या हमारा प्रशासनतन्त्र हमारी इच्छाओं, आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाया है, क्या वह हमारी नीतियों का सही क्रियान्वयन नहीं कर पाया है। यदि हम इसका ध्यान से आंकलन करेंगे गम्भीरता से आंकलन करेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वह व्यक्ति जिसे हम भर-पेट भोजन करने को पर्याप्त नहीं देते वह व्यक्ति जिसे हम अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं देते वह व्यक्ति जिसे हम सम्मान का जीवन जीने की स्वतन्त्रता नहीं देते उससे हम ऐसी आशा और आकांक्षा करें कि वह हमारी नीतियों का क्रियान्वयन हमारी आशाओं और आकांक्षाओं के अनरूप कर लेगा यह सम्भव नहीं है। मैं नौकरशाही का पूर्ण रूप से बचाव नहीं करना चाहता वास्तविकता यह है कि जहां एक ओर नौकरशाह और प्रशासनतंत्र कांच के मकान में रह रहा है वहां दूसरी ओर हम राजनीतिज्ञ भी कांच के मकान में ही हैं। एक दूसरे का पत्थर फेंकना उचित नहीं है। हम दोनों ही गलती पर हैं। हम दोनों ने ही राष्ट्र के लोगों राष्ट्र के नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। इस लिए

4.00P.M

दोनों को बडी गम्भीरता से इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। पर मैं यह बात दृढता से कहना चाहूंगा कि यदि हम चाहते हैं कि नौकरशाही या प्रशासनतत्र हमारी नीतियों का पालन करे, हमारी नीतियों के अनुरूप कार्य करें, हमारी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करे, जो स्वप्न हम अपने नागरिकों के लिए अपनी जनता के लिए देखते हैं उसको साकार करे तो हमें अपने प्रशासनतंत्र को मजबूत रखना होगा, उसे स्वतंत्रता देनी होगी।

बार बार कमिटमेंट की बात होती है। अब लोग यह कहने लगे हैं कि नौकरशाही को कमिटेड होना चाहिए और कमिटमेंट की जो सही परिभाषा है उससे हटकर हम उनसे आकांक्षा करने लगते हैं। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारी नौकरशाही अपने कार्य को सही रूप में करे तो यह कमिटमेंट की हम आशा रखते हैं यह कमिटमेंट किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं होना चाहिए यह कमिटमेंट किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं होना चाहिए, यह कमिटमेंट हमारे संविधान के प्रति होना चाहिए, यह कमिटमेंट राष्ट्र की जनता के प्रति होना चाहिए। यह फिर तभी संभव है जबकि हम प्रशासनतंत्र के अपने नागरिकों को यह आश्वासन दे दें, यह आवश्वस्ति दें दें कि यदि वे निर्भीकता से, निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे तो उन पर आंच नहीं आएगी। इस पृष्ठभूमि में, इस परिवेश के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हम चाहते हैं कि यह प्रशासन तंत्र अपने कार्यों को ठीक से करें यदि हम चाहते हैं कि हमारी नौकरशाही हमारी आशाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप अपने कार्यों का निष्पादन करें तो यह आवश्यक है कि हम संविधान में उन्हें वह संरक्षण दें जो उनके लिए आवश्यक है। उस परिवेश में मैं, हमारे विद्वान मित्र ने जो प्रावधान संविधान में संशोधन के रूप में लाया है, उसका समर्थन करता हूं और ... *(व्यवधान)*

Let the interruptions stop, Sir.

डा० बापू कालदाते : और थोडा चलाइये।

ठाकूर जगतपाल सिंह : आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आप विदड्रा कर रहे हैं।

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : आपको सपोर्ट किया जा रहा है।

श्री अजीत जोगी : परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई थीं, स्थितियां ऐसी बनी थीं, कि संविधान के इस प्रावधान में कुछ संशोधन करने पड़े थे। यदि आप इन संशोधनों की ओर ध्यान देंगे जहां राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, शासन के नियुक्ति कर्ता अधिकारी को ऐसे मूल अधिकार दिये गये हैं जो नौकरशाही को, जो एक अधिकारी को, कर्मचारी को निष्पक्ष रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता संभव होने दें तो ऐसी केवल तीन ही परिस्थितियों का उल्लेख इस संविधान में किया गया था। यदि

[श्री अर्जित जोगी]

किसी व्यक्ति को किसी शासकीय कर्मचारी को दण्ड प्रकरण में सजा दी जाती है यदि किसी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी का कार्य इस श्रेणी का है कि उसे दंड देना तो अनिवार्य हो किन्तु दंड देने के लिए जांच करना राष्ट्र हित में है, जनहित में आवश्यक न हो। जब यह संशोधन किया गया था, तो इन परिस्थितियों को विस्तार से समझा गया था। यह कहा गया था कि कभी-कभी, यदा-कदा, ऐसी परिस्थिति आ सकती है जबकि किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के कार्य-कलापों की जांच करना राष्ट्र के हित में न हो। मान लीजिए, कोई कर्मचारी जासूसी के कार्यों में संलग्न हो और लोगों को पता चले कि उसने राष्ट्र के हित को अपने आर्थिक हित के सामने बेचा है, तो ऐसी परिस्थिति में जांच करके जासूसी के भी मुद्दे, जो लोगों के समक्ष नहीं आना चाहिए, उन्हें सामने लाना सम्भवतः उचित नही होता। इसलिए यह संशोधन किया गया था।

अंत में एक व्यापक अधिकार राष्ट्रपति को और राज्यपाल को यह दिया गया था कि जब उन्हें यह लगे कि राष्ट्र की सुरक्षा के हित में, राष्ट्र की सुरक्षा को बनाये रखने के हित में किसी कर्मचारी या अधिकारी को शासकीय सेवा से पृथक करना है, तो उसके अधिकार उन्हें पूर्णतया दे दिए जायें। मैं यह नहीं कहता कि यह तीनों परिस्थितियां आवश्यक नहीं थीं, मगर मैं यही कहना चाहूंगा कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, ऐसी सामाजिक व्यवस्था में हैं, जो निरंतर अनवरत, अविराम परिवर्तित हो रही हैं, बदल रही हैं, विकसित हो रही हैं।

इसलिए उस समय की परिस्थितियां सम्भवतः ऐसी थी, उस समय राष्ट्र में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई थीं कि कुछ शासकीय सेवकों को इस प्रकार से सेवा से प्रथक किया जाना आवश्यक था, किन्तु आज पुनः वैसी परिस्थितियां नहीं और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती कि इस प्रकार के अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को, दंड देने वाले अधिकारियों को दिये जाएं कि वह बिना कोई जांच किये, बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किये, बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए शासकीय कर्मचारियों और शासकीय अधिकारियों को दंडित करें। यह मेरे दृष्टिकोण से कदापि उचित नहीं होगा।

हमें किसी को दंड देना है, तो यह अधिकार हमारे पास होना चाहिए, नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास होना चाहिए महामहिम राष्ट्रपति के पास होना चाहिए, राज्यपाल के पास होना चाहिए, किन्तु दंड दिए जाने वाले व्यक्ति को भी यह अधिकार होना चाहिएं कि इसके पहले कि उसे दंडित दिया जाए, इसके पहले कि उसे सजा दी जाए, वह अपना पक्ष तो प्रस्तुत कर सके, वह अपने बचाव में तो कुछ कह सके, वह अपने बचाव में अपने साक्ष्य समक्ष में रख सके, वह अपने बचाव में अपने गवाह, अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सके। इतना भी अवसर एक ऐसे व्यक्ति को न देना जिसे अन्यथा भी हमने स्वतंत्र नहीं रखा है, एक ऐसे व्यक्ति को नहीं देना जिसे हमने उसके मूलभूत नागरिक अधिकारों से वंचित कर के रखा है, यह मेरे दृष्टिकोण से सर्वथा अनुचित होगा, उचित नहीं होगा, न्याय के प्रतिकूल होगा और हमारी और आपकी और इस सदन की गरिमा के भी प्रतिकूल होगा।

इन सब बातों को देखते हुए तथा इन सब बातों के परिवेश में, परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने यह जो संशोधन हमारे समक्ष रखा है, उस पर शासन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इस संशोधन का लाभ इस राष्ट्र के लाड़ों, करोड़ों शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा। इस संशोधन से वह अपना कार्य और दक्षता से, और क्षमता से करने को प्रेरित होगें।

इसलिए मैं इस संशोधन का हार्दिक समर्थन करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि इस पर शासन के स्तर पर गम्भीरता से विचार हो। धन्यवाद।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Amendment) Bill brought forward by Dr. Bapu Kaldate. I am in partial agreement with the hon. Member. He wants that in article 311 of

the Constitution, clauses (2) and (3) shall be omitted. The reason given by him is that the ruling of the Supreme Court will definitely stop the flow of efficient and the highly qualified persons into public services and they may go to foreign countries or join the private sector where they are governed by various labour laws and principles of natural justice with better perks and service conditions. This is the apprehension in the mind of the hon. Member and, therefore, he wants that the unbridled power which has been given to the highest authority should be curbed. I would like to point out here that article 309,310 and 311 are the three articles which govern the service conditions of Government servants. Article 310 gives the power of appointment and it also says that a Government servant holds office during the pleasure of the President or the Governor of the State concerned. The appointing authority is the President or the Governor as the case may be with the advice of the Council of Ministers who delegate the powers to the other lower authorities for the purpose of appointment. Under article 311, the main provision which affects the Government servants is proviso (b) of clause (2) which says:

> "where the authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason, to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to hold such an enquiry."

I think, this provision is not protecting even the loyal Government servant. Sir, Government servants can be categorised as higher-level officers, middle-level officers and lower-level officers just as we have the rich people, the middle-class and the lower strata in the society.

Now, Sir, the higher-level officers in the bureaucracy try to suppress the middle-level and the lower-level officers. This power of recording the reasons in writing for not holding an enquiry in the hands of the higher-level officer, that is, the disciplinary authority, against the subordinate officer without any checks and balances will naturally demoralise the Government servants who are working in the lower levels. This is not in tune with the principles of natural justice. A person may be employed in an industry or some other undertaking. In all cases, the procedure as laid down in the Industrial Disputes Act is followed. But in this particular provision, the power which is given to the higher authorities is actually not a satisfactory one. This is because the officers are not above board. There are some good and honest officers in the administration and there are some officers in the administration who are not actually doing good and honest work. When they are doing an illegal act when they compel the officers who are in the middle or lower ranks to tamper with the files and when the officers in the middle rank do not agree to that, the higher officer can make use of this provision for the purpose of victimising the officers who are doing their duty perfectly. Therefore, I would like to submit that this particular provision is actually demoralising the government servants.

Let us go to the views expressed by the framers of the Constitution relating to article 311. Dr. Ambedkar, who is the architect of the Constitution, was pleased to observe that article 311, which embodied guarantees against arbitrary dismissal or removal from service, is probably the best provision that we have for the safety and security of the civil service. This was prior to this amendment. He did not quite reckon with the ways of those rest in a little brief authority. Transfers, suspensions, compulsory retirements and promotions or their denials, have proved their potency as weapons to punish the independent or reward the unworthy. By these powers, he has observed that this particular provision will go to reward the person who is not honest and punish the person who is honest. Therefore, he said that this particular provision is to be amended.

Sardar Vallabhbhai Patel, while writing a letter to our former Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru, on this article, has mentioned in his letter as under:

> "I need hardly emphasize that an efficient, disciplined and contended service, assured of its prospects as a result of diligent and honest work, is a *sine qua non* of sound administration under a democratic regime even more than under an authoritarian rule. The service

[Shri V. Narayanasamy]

must be above party and we should ensure that political considerations, either in its recruitment or in its discipline and control are reduced to the minimum, if not eliminated altogether."

Therefore, the framers of the Constitution were of the view that this particular provision of article 311 (2) (b) will definitely cause injustice to the government servants who are subordinate to the higher authority.

Recently, no issue arose because the authorities in the highest office did not use their powers in the earlier years. The Parsuram's case is a test case relating to article 311 (2)(b) in which the Supreme Court has categorically stated that within the spirit of the Constitution and article 311, authority of the highest office cannot be questioned against disciplinary proceedings. Therefore, the entire dispute arose and various criticisms have come in.

I would like to say that there are more than 12 million government servants employed in the government service. Those employees are doing good and honest work and the Government is also doing very well with them, but for a small act of a government servant the highest officer can victimise him. Therefore, the Government can also come with a policy or even a declaration that official offences can be categorised. What are the grave offences? They can be like selling secret information relating to the government to another person, theft cases or even bribery cases. The case of corruption can be categorised and small petty offences can also be categorised so that the Government servant's security in service can be maintained. This can be given a look by the hon. Minister because in overall view it would go to show that the government servant can be punished under this provision even for a petty offence. I would like to refer to the views expressed by Supreme Court in Tulsi Ram's case. He was an auditor employed by the Government and his salary was not paid. Therefore he went to the Head office and questioned them. He got into an alteration and there he manhandled one of the officers. The authority, without giving him a reasonable opportunity, was pleased to dismiss him from service in pursuance of Art. 311(2) (b) of the Constitution. Then the order was challenged and also the provision was challenged in the Supreme Court. The Court was pleased to dismiss the writ petition. I would like to say that factually the Government also should see whether this provision could be used against the Government servant. For the reasons given in that provision itself, the authority, even without recording the reasons, can dismiss the government servant. That is arbitrary. Whether it is a criminal case or a case coming within the purview of the Industrial Disputes Act there are so many questions to be answered for the purpose of proving the case. In this provision it is absolutely very clear that the authority which is using the power can dismiss the government servant without any reasons whatsoever and thereby the government servant's image and his working conditions will definitely be jeopardised. The principle followed in Art. 311(2) is a part of the legacy of British India wherein government servants were appointed earlier on a contract basis. Thereafter Government of India Act, 1935 came into force on the basis of which government servants came to be appointed during the "pleasure" of the authority which was appointing him. The same principle is being followed under the Constitution. We are actually bringing the spirit behind the Government of India Act, 1935, which was in existence in pre-Independence days, even into our Constitution for the purpose of regulating service conditions. There is no guarantee actually that the government servant will not be victimised.

I would like to pose a question to the hon. Minister: who is to decide whether a government servant has committed a crime or is guilty? The disciplinary authority has to decide. The disciplinary authority is a person who is prejudiced against the government servant. Where the power is vested with a person who is actually prejudiced against the government servant, naturally the government servant will be a

victim in his hands. Therefore the power given to the authority under this provision should be removed and the government should give the government servant a reasonable opportunity, give him a show-cause notice, hear his objections, hold an enquiry and then come to the conclusion. The normal procedures available for any other service or under the Industrial Disputes Act and other Acts have to be thoroughly gone into and should be followed. I would like to say further that this criticism actual-has been not only from the Opposition side but also from our side for the purpose of protecting the interests and welfare of the government servants. Our main concern is that honest Government servants should not become victims in the hands of the highest officers who want to take revenge upon them. Therefore, I would like to submit that this provision under 311(2)(b) may be deleted and the principles of natural justice may be followed. I am not agreeing with the amendment of clause (e) and 3 which is sought by the honourable Member because clause 3 says that if any information that is disclosed will be detrimental to the interests of the nation, the defence and security of the nation and, therefore, that provision should be there in the Constitution. The proviso under article 311 (2) (a) may be removed, and thereby the Government servants will get justice and they can explain their case perfectly well and thereby they will also get themselves satisfied that truth has come out in the course of the inquiry.

With these observations, Sir, I conclude. Thank you very much.

SHRI THANGABAALU (Tamil Nadu): Thank you very much, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I am extremely happy to associate myself with my colleagues and make some observations on this important Bill just as my colleague, Mr. Narayanasamy, has elaborated various legal points through which he wanted to justify the importance and the relevance of the Government servants' interests.

Sir, after Independence we have been giving enough opportunities and a lot of facilities to the Government servants just like other Indian nationals or, I can even say, more. The Government servants in this country are today a privileged class. No doubt, they are working in the interest of the nation, in the interestof the community, so that they should get this privilege. There is no objection, there is no controversy, about that. In that respect, from the very beginning our Government has been giving enough help and showing enough sympathy for the Government servants whether it is of the State or of the Centre.

Sir, here I would like to make one very important point today. What is happening in the Government sector, whether in the Central Government or the State Government, whether it is the public sector or the private sector, totally, in the name of democracy people take more advantage and more liberty even to subvert the interests of the nation. There are people who, in the name of unions forget the interests of the nation and talk only about the interest and welfare of the working class. We never disagreed with the people whether union leaders or others, and the Government, particularly the Congress Government, right from the inception of democracy in this country under the leadership of Panditji and, subsequently, Indiraji and today under the dynamic leadership of Shri Rajiv Gandhi, has been giving the higest priority to this sector. But, Sir, you may be knowing that on many occasions, in our country, many agitations have been taking place for flimsy reasons as compared to other developing countries--which can be averted. As per one statement that the honourable Prime Minister had made in the last session, if our employees, our people, conduct an agitation or a bandh, in one day the country has to lose Rs. 400 crores. Is it in the interest of the nation? is it in the interest of the people? The percentage of the working people to the mass of the country is very very minimal. At the same time, there are other areas, other sections in the country which are not getting the due share of the right and other facilities. For instance, the agricultural labourers, small agricultural farmers are also working day and night, under the Sun and the rain. What is their condition. Are the trade unions of

[Shri Thangabaalu]

even the Government servent leaders taking care of them? They only want their due rights because in this country the organised unions can do everything.

According to the Planning Commission report, there are 50,000 organised unions in this country today. In total, 6 million persons in the organised sector are getting the fruits of the country's labour welfare activities, labour welfare programmes. Is it right on our part to continue with the manner in which we are going ahead? There are 361 million people in the unorganised sector. They are agricultutural laboourers. They are also working. They also should get their due share. In fact, they are doing more than what others are doing, and they are producing country's wealth and food. About the production of the foodgrains, we have achieved the farget, more than what we expected. And that sector is not at all cared for. Therefore, I would request our friends on this side and in that side to bear in mind that giving of this kind of facilities to a particular section should not go on further and further.

The hon. Minister, Shri Kaldate, is asking for withdrawal of the very right of the Government officials. Where is the guarantee that people who work in autonmous bodies, will work properly? The Government has to run it properly. It may not be possible to do so if we remove these clauses. What will happen? There will be no discipline. If there is no discipline, what will happen? Only chaos will result. And particularly today we want the country to prosper, the country to develop, to compute with other nations. Compared to the developed countries even, we have enough manpower we have enough wealth, we have enough strength to stabilise, improve with the advanced technologies, also to sustain the growth and also to develop and compete with other countries today. In the prevailing conditions. If we are not going to adjust or change our attitude in favour of the expectations of the people, certainly we are not doing justice to the majority of the society. Certainly we are not helping our brothers and sisters in the rural areas and in the unorganised sector. That is why I would like to appeal to this House and all the other friends, particularly Dr. Bapu Kaldate that he should not insist that the bill should be accepted.

Another thing . . . (*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY: I will not run away like your Prime Minister.

SHRI THANGABAALU: Don't talk of the Prime Minister. Why are you talking unnecessarily? What is the need of it today?

SHRI V. GOPALSAMY: Because he asked me... (*Interruptions*)

He ran away yesterday. (*Interruptions*) You cannot shout me down. (*Interruptions*)

SHRI ARJUN SINGH: Sir, the hon. Members should also be aware where to say what.

SHRI V. GOPALSAMY: People have given a fitting reply. (*Interruptions*).

SHRI THANGABAALU: What is he talking? Does he think that he is equal to him? I may tell you for the record that nobody is equal to the Prime Minister. Nobody can touch him. Nobody can name him. Nobody can shake him. He has been the leader. He is our leader and he will be our leader and of the country. He will be even leader of the country.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: (West Bengal): He is an Almighty God.

SHRI THANGABAALU: Yes, you have to accept the people's verdict.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Yes, he is superior to everybody. Are you satisfied?

AN HON. MEMBER: He is satisfied and India is also satisfied. You may not be satisfied, but India is satisfied.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: You may think that he is God, but... (*Interruptions*)

SHRI M. M. JACOB: Mr. Das Gupta is not in his seat. He is running ... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Thangabaalu, you continue.

SHRI THANGABAALU: Sir, today in India, as I mentioned earlier, we have got lot of disparities in the pay structure between the employees of the Central Government and the State Governments, between the employees of the Centrally sponsored sectors and the private sector. This anomaly has to be changed. We are aiming at the socialist path for which our forefathers and leaders like Panditji and Indiraji paved the way and have done their best. But, are we doing justice to the weaker sections? Are we doing justice to the village poor workers, particularly the agricultural people? In this respect I would humbly submit that the Government as well as the Parliamentarians should come forward to have an equal opportunity, equal benefit in the wage sector for all working class. There must be a wage revision or a commission should be appointed to go into these details and find out a solution. They must get their due share like others.

Now, as I said the people in the organised sector are the only privileged sections of society. This should not continue for ever. What will happen if the unorganised people, the majority of the people, one day revolt for their just right? We should not create that condition in the country because we are going in the right path of socialistic pattern of society. Our leader, Shri Rajiv Gandhi has been emphasising to go in that direction and has been telling our people, our Parliamentarians, our brothers and sisters, that everyone must be ready to take up the challenges and responsibilities to share the other man's problems.

Now, this is the time to rise and work hard for the welfare of the majority sections in the society. My hon. friend, Dr. Bapu Kaldate has been kind enough to bring this very important Bill before this House. I feel the House should not give him permission to withdraw this Bill. As the hon. Members are aware our party and our Government want to do justice to the working class because they are part and parcel of our life. They are equally important to the society in the nation's development. My hon. friends from other side have advanced many reasons to withdraw this Bill. But it is not agreeable to us. We want to do justice to each and every one of our people in this country. By this attitude on their part the Government servants have come to know who are supporting them and which party is with them. I say it is only the Congress party which has been supporting them always. Our leader, Shri Rajiv Gandhi has done many things for them. It is not the Opposition parties. The manner in which they are advancing reasons to withdraw this Bill itself shows their attitude towards working class.

DR. BAPU KALDATE: I will know at the end.

SHRI THANGABAALU: This shows your sympathy towards them.

DR. BAPU KALDATE: I will cash on it.

SHRI THANGABAALU: You cannot cash on it ... (*Interruptions*)

Nobody can throw bomb. We can tackle everything.... (*Interruptions*). Don't talk about all these things unnecessarily.

SHRI V. GOPALSAMY: What relevant mater he is speaking?

SHRI THANGABAALU: We know what is relevant and what is not relevant.

SHRI V. GOPALSAMY: Without substance you are able to speak.... (*Interruptions*)

SHRI THANGABAALU: We know what for you are shouting..... (*Interruptions*)

You will never get a chance to do anything in this country.

SHRI V. GOPALSAMY: Finally the cat has come out of the bag. It shows the intention of the Government.

SHRI THANGABAALU: It is not the intention of the Government.

SHRI V. GOPALSAMY: But you cannot silence the voice of democracy.

SHRI THANGABAALU: You have raised the name of the president. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Thangabaalu, please continue.

SHRI THANGABAALU: Very irrelevantly he brought the name of the President. It is not right on his part to bring the name of the President. Our Prime Minister has categorically stated that we should not drag the office of the President into these small things. That is why I request the President here. It is not a matter to be discussed. We have no authority... (*Interruptions*)

SHRI M. M. JAOOB: Mr. Thangabaalu, please continue.

SHRI THANGABAALU: If he interrupts me, how can I continue? If I don't answer him he will project some other picture.

While supporting Mr. Kaldate's Bill we are not in agreement with his request for deletion of clause (2) (a) and (b) and clause (3). If these clauses are deleted then there will be disorder and this will be the order of the day. We do not want that kind of chaos to be created in this country. Even now I request him to withdraw his amendments. With these obsrvations....

AN HON. MEMBER: Continue.

SHRI THANGABAALU: If Mr. Gopalsamy has no objection I can continue. But to satisfy him I want to conclude. Sir, I thank Dr. Bapu Kaldate as well as other hon. Members who took part in this discussion.

SHRI V. GOPLSAMY: When Dr. Bapu Kaldate moved the Bill, no Speaker from the Congress side came. (*Interruptions*).

SHRI THANGABAALU: Who says? We are always here. We are sitting here since morning to face you. There are many hon. Members in the House.

SHRI M. M. JACOB: Mr. Vice-Chairman, Sir, I object to what Mr. Gopalsamy said. I did not specially field anybody. Hon. Members give their names when the discussion is going on. What he has said is not true. (*Interruptions*).. Mr. Gopalsamy. you are only trying to vitiate the atmosphere by telling untrue things. (*Interruptions*)

SHRI THANGABAALU: Sir, I do not want to take the time of other friends who want to participate in this very important discussion. In the end, I thank you very much for the time given to me to express my views on this very important Bill.

(Nominated)

SHRI THINDIVANAM K. RAMAMURTHY (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to you for the opportunity given to me. The Constitution Amendment Bill brought forward by Dr. Bapu Kaldate has correctly dealt with the subject in which every citizen of this country is involved and interested. He has correctly come forward to safeguard the interests of the government servants but he has forgotten to give the solution for the problem. If the amendment as moved by him is to be carried out, then what is the way out? He has in his objects and reasons clearly mentioned that this Bill is for safeguarding civil servants from being reduced in status or rank without being given a change of being heard. But what is the correct solution? He has asked for the deletion of the entire article 311(2). He must also consider the problems that would arise if this amendment is carried out and alternative suggestion or alternative arrangement is made in the Constitution and in the service rules. We have a system which is in existence for long, which is age-old. He has correctly put it

that the previous Governments have put the civil servants at the mercy of the higher ups in the heirarchy leaving little hope for them. Who are these higher up and what is this heirarchy? Do they stand as the level of the Chief Secretary or the Government or at the department level? If it is the Collector's office, the Collector is the higher up. At what level we have got to safeguard the civil servants, that is the first thing that has to be considered. If this safeguard is given, what will be the effect of it. I mean the problem that would arise out of this. We have got a peculiar system. Dr. Bapu Kaldate said that this ruling of the Supreme Court will definitely stop the flow of efficient and highly qualified persons into public service and they go to foreign countries and join private sector service where they are governed by various labour laws and principles of natural justice with better perks and service conditions. What is happening today is in many cases the retiring officials go into the private sector companies and accept big positions there. If my information is correct, every retired Chief Engineer of the Electricity Board in Tamil Nadu is a director or an important functionary in one private company or other or is a big contractor. That is how he ends up. So also some of the IAS officers, after retirement, are holding very high positions of directors in private companies. How do you account for their character or their method of functioning all through their service? Can this go on happening unchecked? We have another example also. In many States there are now five or six DGPs, there are eleven to twelve Chief Secretaries. If promotion alone is taken into consideration, by amendment, if you ensuring their promotion alone, that alone will not satisfy the officers. There are many officers in the States who are promoted but who, on promotion, are put in charge of departments which do not qualify for being put into the hands of such senior officers, which do not need to have such high experienced officers. I can cite one peculiar example in our State. A few years back there was a scheme known as Veeranam Water Scheme for bringing water for Madras city. The officers who had worked this scheme, who had prepared the project report and said it was feasible, it was most important, economically viable, and so on, after that Government went out those very officers came out with another report saying that it was not feasible, it was meant for some other purpose, that there was corruption and nepotism on the basis of which the entire project was prepared. This was the statement issued by the very same officers. There is similarly another example in Tamil Nadu that of Kattalai canal which was projected but which ultimately did not come through. When the project report was prepared everybody wondered whether it would go through, whether it was a feasible project, whether it should be thought of at all. The officers involved in the project gave a very fitting reply saying that was the best scheme which would solve the water scarcity problem in Madras city, and that it was feasible, essential and should go through. But after one year the very same engineers involved in it, including the Chief Engineer, if I am correct, gave a report that Kattalai Canal could not go through, it was not feasible, it was not warranted, it would not solve the water scarcity problem of Madras city. Furthermore, they said the very basis of the project report was wrong. So it is evident that we have a band of officers who can act to the tune of the person in power. So, this should be put an end to. So, an amendment, as Dr. Bapu Kaldate has thought of, will not save us from the problems of this kind. So, if we are to get out of this problem and we have got tofind a solution which will safeguard the interests of the civil servants and, at the same time, will see to it that the officers concerned involve themselves in their duties

[Shri T. K. Ramamurthy]

and nothing more and will see to it that corruption and nepotism are wiped out from the services. In the statement of Objects and Reasons, Dr. Kaldate has said that the conduct rules governing the service conditions of the Government employees which were framed by the British to keep the Indian bureaucracy under their thumb are still being continued in varying degrees by successive Governments even after 38 years of independence. So, he is not angry with either this Government or any other Government. He has the experience of his own Janata Government also and he must have had or at least his party members must have had an opportunity or occasion to bring forward a legislation of this kind. Anyway, today he has brought forward this amendment and I am sure that it is not that he wants this to be enacted immediately, but wants to draw the attention of the House to this problem and to find a solution to this problem through a discussion like this and that is how I take it. I am saying this because he has rightly pointed out that the ruling of the Supreme Court will definitely stop the flow of efficient and the highly qualified persons into public services and they may go to foreign countries or join the private sector. It is not only that. There are people who go over to the private sector and there is no dearth of such people. But what is important is how they come to it. There are people wro come out in the middle of their service. What is the percentage of such people? Dr. Kaldate should take into account the percentage of people who get employment after retirement, and they get employed after retirement in companies whose files they were dealing with, in the newspapers at whose mercy they were having their entire service and in engineering concerns for whom they were alloting contracts and this is how it goes on. Why should it not be checked and how should it be checked? That is the question. Will the solution sugegsted by Dr. Kaldate end the problem? It will not. On the other hand, it will increase this problem and it will increase the confusion. Even though Dr. Kaldate has come out with this amendment to make this House think of this problem, it is all the more necessary and important that this House also thinks of getting out of this situation. In other words, we have to find a solution which will ensure the interests of the civil servants and the interests of the nation. Both should go together.

There is another thing which I would like to point out. There are officials who are enjoying all the benefits. They are there and we must give them all the benefits.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Sir, Mr. Ramamurthy is making very good points and so, he can continue his speech next week, Mr. Ramamurthy. You are giving a thoughtful proposition.

SHRI THINDIVANAM K. RAMAMURTHY : Thank you very much. I wish I am given the opportunity next time also.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO : You can continue next week.

SHRI THINDIVANAM K. RAMAMURTHY: That is why I am continuing now.

Now, Sir, there are officers who deal with co-operative societies, housing, etc and it becomes so convenient for them to make themselves suitable according to the occasion and then to act or work accordingly. In our experience, Sir,....

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : Mr. Ramamurthy you can continue next time.

ANNOUNCEMENT RE: ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 16th April, 1987, allotted time for Government Legislative and other Business as follows: